(ख) सरकारी अस्पतालों में उपस्करों का रख-रखाव और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। जब कोई उपस्कर खराब हो जाता है तो संबंधित संस्था/अस्पताल द्वारा वार्षिक सेवा संविदा पर मुख्यतः निर्भर करते हुए यथाशीघ्र संभव समय में मरम्मत कराई जाती है।

पब्लिक स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण

533. **प्रो० रामगोपाल यादवः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का पब्लिक स्कूलों पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो अदालती आदेश की खुली अवहेलना कर जबरन फीस के रूप में मोटी रकम वसूलने के खिलाफ क्या सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु तत्काल कोई कदम उठाएगी जिससे मध्यम एवं सामान्य वर्ग के लोगों को राहत मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) पब्लिक स्कूलों पर नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के शिक्षा अधिनियम में किये गये उपबंधों के अनुसार और उस बोर्ड के संबंधन उपनियमों के अनुसार किया जाता है जिससे स्कूल संबद्ध होते हैं।

(ख) और (ग) शुल्क इत्यादि लेने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पास किये गये आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्रीय सरकार को ऐसे कोई निदेश उच्च न्यायालय से नहीं प्राप्त हुए हैं।

तकनीकी शिक्षा का विकास

534. **श्री बालकवि बैरागीः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1996-1997, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी उच्च शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र सरकार को कौन-कौन सी योजनाएं प्रेषित की हैं;

(ख) उनके द्वारा उक्त योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से मांगी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन से राज्यों की कौन-कौन सी योजनाओं को कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) स्वीकृति के लिए विचाराधीन योजनाएं राज्यवार कौन-कौन सी शेष हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) तकनीकी शिक्षा परियोजना 1 तथा 2 के अंतर्गत; भारत में पॉलिटैक्निक शिक्षा का उन्नयन करने के लिए 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक कार्यान्वयनाधीन परियोजना के तहत विश्व बैंक द्वारा निधियां प्रदान की गई हैं।

इस परियोजना के तहत पॉलिटैक्निक शिक्षा में प्राप्त लाभों के कायम रखने लिए इस मंत्रालय ने तकनीकी शिक्षा परियोजना नामक एक अन्य परियोजना के लिए नई विदेशी सहायता का प्रस्ताव किया है जिसमें लगभग लगभग 10 चुनिंदा पॉलिटैक्निकों को उत्कृष्टता के केन्द्रों में बदलने, कुछ भारतीय पॉलिटैक्निक संस्थानों की स्थापना करने और कार्यान्वयनाधीन परियोजना के तहत शामिल न किये गये राज्यों को शामिल करने का कार्य निहित है। विभिन्न राज्य सरकारों से मांगी गई निधियों की आवश्यकता के अनुमानों के आधार पर एक समेकित परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक से सहायता की मांग करने के लिए तैयार कर लिया गया है।

Drop out Rate

535. **DR. (Ms.) P. SELVIE DAS:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) how many children in the age groups 6—10 and 11—13 years, were out of school in the Eighth Five Year Plan period State-wise and sex-wise; and

(b) the number of children dropped out by the age of 10 years, sex-wise and state-wise?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI):

(a) According to available information the estimated number of out of school children in the age group of 6—11 and 11—14 years are 3 crore and 3.3 crore respesctively. State-wise and sex-wise details of these children are, however, not available.

(b) A statement showing the drop out rate in classes I—V for the year 1996-97 sex-wise and state-wise is attached. (*See* below) However, information about age-specific enrolment is not collected and hence age wise dropout is not calculated.

Statement

Drop-out Rates in Classes I to V for 1996-97 (Provisional)

Sl No.	State/UT	Boys	Girls
1.	Andhra Pradesh	45.34	48.30
2.	Aruchanal Pradesh	53.74	48.60
3.	Assam	39.82	41.74
4.	Bihar	60.85	63.44
5.	Goa	2.74	9.52
6.	Gujarat	41.20	46.39
7.	Haryana	17.03	20.80
8.	Himachal Pradesh	21.33	30.05
9.	Jammu & Kashmir	34.40	33.63
10.	Karnataka	40.91	45.51
11.	Kerala	*	*
12.	Madhya Pradesh	25.97	38.29
13.	Maharashtra	18.65	25.60
14.	Manipur	41.12	43.68
15.	Meghalaya	59.45	62.45
16.	Mizoram	59.14	56.95
17.	Nagaland	38.53	34.12
18.	Orissa	50.75	47.90
19.	Punjab	24.03	21.76
20.	Rajasthan	48.79	57.02
21.	Sikkim	61.88	55.40
22.	Tamil Nadu	14.05	16.21
23.	Tripura	52.73	56.65
24.	Uttar Pradesh	22.31	22.94
25.	West Bengal	55.83	55.59
26.	A & N Islands	19.77	21.01
27.	Chandigarh	0.13	2.76
28.	D & N Haveli	32.57	47.55
29.	Daman & Diu	3.13	*
30.	Delhi	11.62	23.50
31.	Lakshadweep	5.44	*
32.	Pondicherry	*	*
	India	39.37	38.35

*There is no positive growth during this period.

Vacant posts of KV teachers in North-East

536. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of Kendriya Vidyalayas functioning at present in the North-eastern Region;

(b) the total number of posts of TGT, PGT, etc. lying vacant in those Vidyalayas for the last five years, category-wise;

(c) the reasons for not filling-up these vacancies in all the Vidyalayas during this period; and

(d) the necessary steps being taken/proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) The number of Kendriya Vidyalayas functioning at present in the North-Eastern Region is 82. (Eighty Two).

(b) to (d) Total number of posts of Trained Graduate Teachers and Post Graduate Teachers which could not be filled up, on regular basis, are 202 and 197 respectively. However, short-term appointments on contracts basis have been made against majority of such vacancies in order to avoid disruption in studies of students. Vacancies could not be filled up, on regular basis, mainly because of non-availability of suitable candidates from respective Regions.

The exercise for recruitment to the post of Post Graduate Teacher has since reached an advanced stage. For other category of teachers also an open advertisement is being issued in leading Newspapers.